© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

भूमंडलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

डॉ0 श्रवण कुमार
पूर्व शोध छात्र, शिक्षा संकाय,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत।

20 वीं शताब्दी के अंतिम दशकों व 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में आवागमन, सम्प्रेषण तथा उत्पादन के आधुनिक साधनों ने विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव उत्पाद व सेवा की पहुंच अत्यधिक सहज ढंग से सुलभ करा दी है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व एक गॉव के रूप में देखा जाने लगा एवं आर्थिक पक्षों में एक नया युग प्रारंभ हो गया है। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण इसी आर्थिक संक्रमण की परिणति है। शिक्षा का क्षेत्र भी इन प्रवृति से अछूता नहीं रहा है तथा आज शिक्षा संबंधी चर्चा में इन तीनों शब्दों का बहुतायतः से प्रयोग होने लगा है।

भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से तात्पर्य संपूर्ण विश्व को एक दृष्टि से देखने व परस्पर सक्रिय सहयोग देकर सबका हित करने से है। सिद्धांत रूप में भूमंडलीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सभी राष्ट्र विभिन्न क्रियाकलापों में घुल–मिल कर समरस हो जाते हैं। यह उस व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है जहॉ विभिन्न राष्ट्र संस्थाऍं व नागरिक विभिन्न राष्ट्रों का खुलकर सहयोग लेते हैं । यह विचारधारा भारतीय संस्कृति में ''वसुधैव कुटुम्बकम'' के भाव के रूप में हजारों वर्षो से विद्यमान है, जिसका पाश्चात्य देश अब अनुकरण कर रहे हैं। भूमंडलीकरण ने रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा अभियांत्रिकी, व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में अनेक नयी संभावनाओं को तलाशा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक संस्थाओं ने अन्य राष्ट्रों में अपनी पहुंच बनायी है तथा वहॉ के नागरिकों को शिक्षा सुविधाऍं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भूमंडलीकरण निःसंदेह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में विश्वव्यापी सहयोग, सक्रियता व समायोजन की प्रक्रिया कही जा सकती है।

भूमंडलीकरण वर्तमान समय के व्यापारिक माहौल की ऐसी अवधारणा है जो पूरे विश्व को एक मंडल, एक केंद्र बनाने की बात करती है। आज भूमंडलीकरण प्रत्येक क्षेत्र का मुख्य विषय बन गया है क्योंकि इसने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को अत्यंत प्रभावित किया है। जैसे –रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गरीबी पर प्रभाव, अर्थव्यस्था पर प्रभाव, महिला वर्ग पर प्रभाव व समाज के गरीब, दलित, कमजोर वर्ग पर प्रभाव तथा मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा पर प्रभाव। यदि हम अवलोकन करें तो पाते है कि बाजार की नीतियॉ सभी स्थानों पर लागू होती है चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। अतः शिक्षा मानव विकास की रीढ़ है। हमारी शिक्षा की प्रशासनिक ढांचा ही यह सुनिश्चित करता है कि समाज के बहुमुखी विकास में हम युवाओं को उपयोगी शिक्षा देने में कितने सक्षम है।

यह बात सभी स्वीकार करते है कि सुव्यस्थित और सुसंस्कृत संपूर्ण विकास के लिए अच्छी शिक्षा परम आवश्यक है। परंतु भूमंडलीकरण की इस मार से देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा भी नहीं बचा है। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व उच्च

शिक्षा की स्थिति में जहॉ एक ओर सुधार हुआ है वही पर शिक्षा के निजीकरण के कारण साक्षरता दर में आशानुरूप सुधार हुआ है। आज भी 29 करोड से अधिक प्रौढ लोग निरक्षर बने हुए है एवं लगभग 3 करोड़ 80 लाख बच्चे विद्यालय का मुंह नही ंदेख पाते है। वर्ष 1996–1997 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 3.8 प्रतिशत शिक्षा पर लगा। इसी कारण प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देने के शोर के बीच वास्तव में 1990 के दशक के दौरान प्रारंभिक शिक्षा प्रचार में सार्वजनिक खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद को 1.69 फीसदी से घटकर 1.47 फीसदी हो गया है। शिक्षा एवं साक्षरता के प्रति ऐसे रवैये के बीच करोड़ों लोगों को निरक्षरता को अंधेरे में डूबोये रखकर हम सूचना प्राधौगिकी की चमक यहॉ बिखेरना चाहते है। मौलिक अधिकारों के अनुसार–शिक्षा पर सबका समान अधिकार हैं। परंतु अब यह मौलिक अधिकार में ही मात्र धनी वर्ग का अधिकार बन गया है। शिक्षा को सार्वजनिक पकड़ से दूर कर इसके निजी–एकाधिकार पर अधिक बल दिया जा रहा है। शिक्षा का बजारीकरण कर निजीकरण करने का तमाम बातें चल रही है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा बाजार की वस्तु हो जायेगी। विद्यालय, महाविद्यालय दुकान हो जायेंगे और इस सबकी नकेल किसी बडी कंपनी के हाथों में होगी। अतः वैश्वीकरण की नीतियॉ आम जनता के हित में नहीं क्योंकि वैश्वकीकरण प्रकृति के साधनों को बेरहमी से लूटता है और वह हथियारों की शक्ति, पूॅजी की शक्ति, और विज्ञान की शक्ति से कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाता है।

भूमंडलीकरण का यह प्रभाव यह भी है कि शिक्षा पर दी जानेवाली सब्सिडी में कटौती हो रही है। शिक्षा को ठेके पर दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है क्योकि समाज के एक वर्ग का मान्यता है कि समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जबकि वास्तविकता यही दर्शा रही है कि निजीकरण केवल मध्यम तथा उच्च वर्ग को ही फायदा पहुंच रहा है। आज देश में 36 करोड़ लोग अशिक्षित है, ये सरकारी आंकड़े है तथा अर्थात में परिदृश्य और भी भयानक है। देश के करीब 260 विश्वविद्यालयों की अस्मिता खतरे में पड़ गयी है।

स्वास्थ्य, रक्षा, दूरसंचार और वित्त के साथ ही विद्यालय की शिक्षा ही 1994 के गैट प्रावधान में शामिल थी और अब डब्लूटी0ओ0 के सदस्य देशों में 40 देश इस बात पर पर तैयार हो गये है कि गैट के तहत खुलनेवाली सेवाओं में शिक्षा को भी शामिल किया जाये। जिसके परिणामस्वरूप कुछ मुट्ठी भर कंपनियॉ को खुली छुट मिलेगी और इच्छानुसार शाखा खोलकर शिक्षा देंगी जो खास प्रणाली पर आधारित होगी और यथार्थ का दृष्टिकोण पेश करेगी।

देश में शिक्षा के क्षेत्र मे ंसमानता होने के बजाए असमानता बढ़ रही है। जहॉ 1991 में राजस्थान के आदिवासियों के बीच साक्षरता दर 19 प्रतिशत वहीं पर मिजोरम में 80 प्रतिशत। आज भारत महंगी शिक्षा पद्दति के कारण एक तरफ धनिक दूसरी तरफ निर्धन लोगों का देश बन कर रह गया है। अब शिक्षा प्राप्त करना गरीबों के वश की बात नहीं है। विश्वविद्यालय में सरकार सब्सिडी की कटौती कर रही है, जिससे विद्यालयों, महाविद्यालयों की फीस में कई गुणा वृद्धि हो रही है। अतः विश्व की बहुसंख्यक के लिए वैश्वकीकरण में अच्छे और लाभकारी परिणाम नहीं पैदा किये, बल्कि देशों के अंदर तथा देशों के बीच आमदनी की असमानताऍ, विश्व में 20 प्रतिशत अमीर देशों की जनसंख्या तथा गरीब से गरीब देशों की संख्या की आमदनी का अंतर 1960 में 30.1 से 1995 में 82.1 हो गया है ंतथा तीसरी दुनिया की हाल और भी खराब हो गयी है। पिछले 20 वर्षो से 70 देशों से भी अधिक में प्रति व्यक्ति आय कम हुई, विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा भाग अर्थात 3 अरब लोग दो अरब डालर प्रतिदिन की आय पर

जी रहे है तथा 80 करोड़ लोग भोजन की कमी से पीड़ित है। तीसरी दुनिया में बेरोजगारी तथा आर्थिक रोजगार की भरमार है क्योंकि विशिष्ट वर्ग की समृद्धि के साथ साथ बडे भारी स्तर पर गरीबी विद्यमान है ।

एक तरफ जहॉ देश की सरकार के पास शैक्षिक गतिविधियों को देख रेख करने हेतु भारी भरकम मंत्रालय है, लेकिन दूसरी ओर वह शैक्षिक सुधारों पर नीति रिपोर्ट तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों और एजेंसियों का सहारा ले रही हैं, तो क्या यह समझ लेना चाहिए कि अब सरकार से शैक्षणिक कार्य नहीं हो पा रहे है और इसलिए यह अपने संस्थाओं को निजी क्षेत्र के नियंत्रण में करती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 838 संस्थाओं में से सिर्फ 230 संस्था ही सरकार के अधीन है। बाकी सब निजी क्षेत्र के नियंत्रण में है। जिसके परिणामस्वरूप ये संस्थान डोनेशन के रूप में मोटी रकम लेकर प्रवेश दे रहे हैं। इसलिए कैसे भरोसा किया जाए कि निजी क्षेत्र के नियंत्रण के संस्थान भी भविष्य में भी अच्छी शिक्षा प्रदान करें।

वर्तमान वैश्वकीकरण के दौर में शिक्षा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक और तेज गति से हुआ है। शिक्षा स्तर व गुणवता के मध्य खाई बढ़ी है। यहॉ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही आधुनिक सूचना व संचार माध्यमों द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं देश के अधिकतर बच्चे खुले आसमान के नीचे बिना कॉपी किताब के शिक्षा प्राप्त करने को बाध्य है।

इस व्यवस्था ने शिक्षित युवा को इतना प्रभावित किया है कि शैक्षिक बेरोजगारी की प्रवृति बढ़ रही है। उद्योगपति अपने उद्योगों में देश के कुछ प्रमुख व ख्याति प्राप्त विद्यालयों से ही रोजगार दे पाने में सक्षम होते है तथा असंख्य विद्यार्थी व्यावसायिक डिग्री लिये दिशाहीन होकर सड़कों पर घुम रहे है तथा यह सब शिक्षा का भूमंडलीकरण का विपरित प्रभाव ही पड़ा है। पिछले दशक के दौरान जहॉ शिक्षा के क्षेत्र में लिंग अंतराल कम हुआ है वही अधिकांश दक्षिण एशिया, अफ्रीका के उप –सहारा तथा अनेक दूसरे विकासशील क्षेत्र में लड़कियों के अपेक्षाकृत अपेक्षित स्थिति में उन्हें माध्यमिक शिक्षा से वंचित कर देती है। वर्ष 2000 में 18 प्रतिशत पुरूषों की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी थी जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी।

निजी संस्थान दिनोंदिन बढ़ते जा रहे है। जहॉ समाज के एक वर्ग की नजर में ये सही है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही है तो फिर प्रश्न यह उठता है कि संस्थान जो दुकान का रूप ग्रहण कर रहे हैं, क्या ये गरीब,अल्पसंख्यक, दलित और पिछडे वर्ग को निःशुल्क शिक्षा दे पायेंगे? नहीं, जबकि सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति को विद्यार्थी को शिक्षा के समान अवसर दिलाने के लिए सचेष्ट रहना पड़ता है। आजादी के 57 वर्षो के पश्चात भी देश के बहुत से विद्यार्थी आरक्षण व वजीफे की व्यवस्था के कारण ही अपनी शिक्षा पूरी कर पाते है और निजी संस्थान किसी को भी इतनी सुविधाएँ प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने आर्थिक आमदनी से अधिक मतलब होता है।

संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार सरकार अपनी समर्थ के अनुसार सभी को शिक्षा से पुष्ट करेगी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है, तब वह दिन दूर नहीं जब इतिहास स्वयं को दुहरायेगा अर्थात पहले की तरह शिक्षा केवल धनी वर्ग तक ही सीमित होकर रह जायेगी क्योंकि ये शिक्षा के नाम पर लाखों में फीस लेते है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, निर्धन युवा वर्ग को जो इतनी महंगी फीस जमा नहीं कर सकते। गरीब प्रतिभाशाली व्यक्ति एक अभिशाप बनकर रह गया है। इन्हीं संस्थाओं के कारण घर बैठे डिग्री खरीदी जा रही है।

भूमंडलीकरण के इस दौर में शिक्षा, अभिभावक तथा विद्यार्थी इन तीनों का इन महंगे निजी स्थानों के कारण मानसिक तथा आर्थिक शोषण हो रहा है, क्योंकि शिक्षा समाज का दर्पण है और विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग ही भावी समाज का निर्माण करते हैं । इनके प्रभाव का कारण संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व पर खतरा मंडरा रहा हो चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हों या राजनैतिक क्षेत्र या सामाजिक व शैक्षिक क्षेत्र में हो । इस तरह प्रतीत होता है कि निरक्षता की भीषण चुनौती भारत के लिए 21वीं सदी में भी पूरी व्यापकता से बरकरार रहेगी।

आज का निजीकरण मात्र यही चाहता है कि उनकी हित साधक बने । संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया में फंसता जा रहा है। आम लोगों को दरकिनार कर निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आज आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को नियम से बाधित कर दिया जाये। क्योंकि सभी यह स्वीकार करते है कि संपूर्ण विश्व साथ चलने के लिए निजीकरण आज की आवश्यकता बन गयी है। इसलिए विश्व के सभी देश में तीव्र गति से हो रहे आर्थिक परिवर्तन को इस युग में यह आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अनुकूल सुधार करें, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अपनी गरिमा स्थापित करनेवाला भारत का भविष्य और भी अंधकारमय व कष्टकारी हो सकता है।

आज की शिक्षा मैकाले पद्दति के आधार पर दी जा रही है। अंग्रेजों के व्यवस्था बनाये रखने के लिए अंग्रेजी बाबू का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्रवर्तकों, नियंत्रकों के देश में आधारित होती है और इन रास्तों पर राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था पर दबदबा इन कंपनियों का ही रहता है। अतः युवा वर्ग को देश व समाज के यथार्थ से दूर रखा जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियॉ में नौकरी पाना एकमात्र इनका लक्ष्य बन गया है। जिस कारण आज अपने ही देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों में न तेा देश की समस्या व चुनौती से जूझने का साहस है और न आत्मविश्वास ही है।

शिक्षा के जरिये, व्यक्ति तंगी और निम्न आर्थिक स्तर से निकलकर जीवन में आगे बढ जाता है। इस प्रकार शिक्षा मानव को गतिशील बनाती है। भारत औद्योगिक विकास करने की हरसंभव कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसे शिक्षित जनता की सख्त जरूरत है ना कि भूमंडलीयकृत कुंडित बाजारू व्यक्ति की। शिक्षित मानव आय का स्रोत ढूंढकर गरीबी को भगा देता है। भूमंडलीय की व्यवस्था ने शिक्षा को जिस रूप में लाने की कोशिश की है वह अत्यंत विचित्र स्थिति पैदा करती है क्योंकि किसी भी प्रकार के विकास में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा विकास का प्रमुख साधन है। मानव और उसके विकास में सर्वप्रमुख स्थान है शिक्षा का। भारत इस दौर में पिछड़ न जाए। इसके लिए आवश्यक है कि देश में सही शिक्षा नीतियों के अंगीकरण द्वारा शिक्षा का न केवल विस्तार हो अपितू उनमें गुणात्मक सुधार लाने के भी प्रभावी उपाय किये जाय।

यह बात सही है कि भूमंडलीकरण के इस ऑधी के आवेग से शिक्षा जगत भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षा संस्थाऍ फैशन स्थलों में बदलती जा रही है, भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है। सांस्कृतिक पतन तेजी से हो रहा है तथा इतिहास के नायकों के स्थान पर हैरी पाटर जैसे किरायेदार हावी हो रहे है। ऐसा नहीं है

कि भूमंडलीकरण की अवधारणा पर जोर देने के कारण शिक्षा जगत में केवल नकारामक परिणाम ही सामने आये है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कुछ शिक्षा संस्थाओं ने अपनी शैक्षणिक स्तर को सुधार कर विश्व को सर्वश्रेष्ठतम शिक्षा संस्थाओं में अपने को शामिल किया है तथा उनसे निकले छात्र–छात्राओं ने अपनी प्रतिभा व योग्यता की धाक संपूर्ण विश्व में स्थापित कर दी है। शिक्षा के भूंमंडलीकरण ने शिक्षा के अनेकानेक न्यूनतम आयामों को जन्म दिया है। भूमंडलीकरण के कारण ही हमारे पाठयक्रम मे, हमारी शिक्षण विधियों तथा हमारी परीक्षा प्रणाली में सुधार आया है। आज हम सूचना व सम्प्रेषण की आधुनिकतम प्रौधोगिकी का प्रयोग शिक्षा में कर रहे हैं, मुक्त व दुरूस्त शिक्षा प्रणाली को बढावा दे रहे हैं ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाएँ संचालित कर रहे हैं, इ–लर्निंग व वर्चुअल विश्वविद्यालय की संकल्पना को साकार रहे है तथा इंटरनेट व ब्रॉडबैंड की सहायता से दुनिया भर की साहित्य व सामग्री घर बैठे पढ़ रहे है। यह सब शिक्षा के वैश्वकीकरण की दिशा में उठाये गये कदमों का ही परिणाम है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप शिक्षा भी व्यापार की एक वस्तु सेवा बन गयी है तथा अन्य वस्तुओं के समान इससे संबंधित विभिन्न सामाग्री व सेवाओं का संपूर्ण विश्व में आयात–निर्यात प्रचुरता से तथा मात्र आर्थिक लार्भाजन के लिए किया जा रहा है । शिक्षा को वाणिज्यिक वस्तु मानना भारतीय परंपरा के विपरीत होने के कारण इस संबंध में अनेक आपत्तियॉ की जा रही हैं । शिक्षा का भविष्य क्या होगा इसका अनुमान लगाना निःसंदेह आज एक कठिन कार्य बन गया है।

संदर्भ सूची :–

1. अईयर, बैद्यनाथ आर0बी0बी0 –भारत में शैक्षिक, नियोजन और प्रशासनः अतीत और भविष्य
2. गुप्ता, रामबाबू– भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामायिक समस्याएँ, आगरा : रत्न प्रकाशन मंदिर
3. गुप्ता, एस0पी तथा अल्का गुप्ता (2008)– भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आगरा : शारदा पुस्तक भवन
4. कुरूक्षेत्र (2004) सितंबर,मासिक पत्रिका
   योजना (2005) सितम्बर,मासिक पत्रिका
5. Dinesh , D Harsoleker (2000)-Globalisation of India Higher Education, University, News Vol 38 (28)
6. Joshi B.H (2000)-Changny Demographic Structure of India, Jaipur, Raj Publicity House.
7. Diobgaonkhar D. (2004)- Higher Education in India "the varied Dimension in University News 42 (21)
8. http://him.wikipedia.org.